



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम - 695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/100833/60

788/789
11/9/24

06.09.2024

To,

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant Of Medical Allowance & Homely Orderly Help Allowance to the Jharkhand State Judicial Service Pensioner/Family Pensioner's w.e.f. 01.01.2016 - reg.

Ref: Letter No. Pen-V/Judiciary/SSA-20/2024-25/678 dated 16.07.2024 received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand.

I am to enclose herewith the copy of Special Seal Authority received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand regarding the grant of medical allowance & homely orderly help allowance to the Jharkhand State Judicial Service Pensioner/Family Pensioner's w.e.f. 01.01.2016. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl.: As stated above.

Yours faithfully

R. John
10/9/24
Senior Accounts Officer

Copy to: -

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)
Jharkhand, Ranchi **-For Information**

sdl -
Senior Accounts Officer

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड का कार्यालय, राँची
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) JHARKHAND, RANCHI



P.19
100833
31-07-2024

77
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

No. Pen-V- Judiciary/SSA-20/2024-25/ 678

Dated: 16-07-2024

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Haidrabad	500004
2.	Director of Audit & pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Nahariagun	791110
3.	Principal Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Principal Accountant General (A&E), Bihar, Birchand patel Marg, R-Block, Patna	800001
5.	Principal Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Principal Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navrangpura, Ahmedabad	380009
8.	Principal Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot N0. 4&5, Sector 33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box N0.-5 Bangalore	560001
12.	Principal Accountant General (A&E), Kerla, Post Box N0. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Principal Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Principal Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Principal Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinther, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Principal Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Principal Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector 17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, deoral, PO- Tadong, Gangtok	737102
24.	Principal Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Annasalai,	600018

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkahnd)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

	Teynampet, Chennai	
25	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Principal Accountant General (A&E), Utter Pradesh, Audit Bhawan Vibhuti khand, Gomti Nagar, Lucknow	226010
27.	Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, N0 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, Tis Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chankyapuri, New Delhi	110021

Subject:- Grant of Medical Allowance & Home Orderly Help Allowance to the Jharkhand State Judicial Service Pensioner/Family pensioner's w.e.f. 01.01.2016

Sir,

I am enclosing herewith the copy of Government of Jharkhand, Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa Vibhag L. N0 1459 Dated 27.02.2024 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl: As stated above

Yours Faithfully


St. Accounts Officer/ Pen-5

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय:- झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी अनुशंसाएँ एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 1022/1989 (All India Judges Association Vs Union of India and Ors.) में दिनांक 06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4598 दिनांक 29.08.2006 निर्गत है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी अनुशंसाओं एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P(Civil) No.643/2015, All India Judges Association Vs Union of India and Ors. मामले में दिनांक 04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भत्ते एवं सुविधाएँ निम्न रूप में देय होंगे :-

1. **गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) :-** झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भारत सरकार के House Building Advance Rules, 2017 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निजी व्यक्ति से Ready Build House क्रय करने की अनुमति अनुमान्य होगी।

अथवा

झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को Advance की सुविधा अनुमान्य होगी। राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की भाँति गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) की सुविधा अनुमान्य होगी।

II. **बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance):-** राज्य के प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) 2019-20 के प्रभाव से निम्न रूपेण Children Education Allowance अनुमान्य होगा।

(i) कक्षा 12 तक दो बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति माह 2250.00 रु0 शैक्षणिक भत्ता एवं प्रतिमाह 6750.00 रु0 छात्रावास सब्सिडी अनुमान्य होगा।

(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति उपर्युक्त उल्लेखित दर से दुगुनी होगी।

(iii) महँगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर भत्ते और सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

जिन पदाधिकारियों को यह लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है उनपर अनुशंसा का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

III. नगर प्रतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) :- आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर प्रतिपूरक भत्ता को समाप्त किया गया है, परन्तु भुगतान किये गये नगर प्रतिपूरक भत्ते की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से नहीं की जायेगी।

IV. अतिरिक्त प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance) :-

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का अतिरिक्त पद के कार्य के प्रभार में 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि तक कार्यरत रहने तथा पर्याप्त न्यायिक कार्यों के संपादन करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के न्यूनतम वेतनमान के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा एवं सम्पादित प्रशासनिक कार्यों के आधार पर अतिरिक्त प्रभार भत्ता देने का निर्णय डारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

V. वाहन/परिवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance):- राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पूर्व से निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित रूप से वाहन सुविधा/परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) पुल कार की सुविधा को समाप्त की जाती है। राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी अपनी इच्छानुसार इस सुविधा को एक वर्ष या इससे अधिक समय तक के लिए जारी रख सकते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों का स्वयं के वाहन के रख रखाव एवं चालक के वेतन हेतु प्रदान किया जान वाले परिवहन भत्ता को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से 10,000.00 रु० से बढ़ाकर 13,500.00 रु० प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक परिवहन भत्ता 10,000.00 रुपये की दर से अनुमान्य होगा।

वैसे न्यायिक पदाधिकारियों का सरकारी चालक या वाहन चालन जाननेवाले परिवारक/आदर्शपाल आवंटित हैं, उन्हें प्रतिमाह 4,000 रु० का परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

- (iii) परिवहन भत्ता के अतिरिक्त शहरों यथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1994/वि० दिनांक-29.06.2010 एवं संकल्प संख्या-400/वि० दिनांक-02.02.2017 के अनुसार 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

- (iv) प्रधान जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/निदेशक, Judicial Academy/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक स्वतंत्र वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय उक्त सूची को कम कर सकती है।
- (v) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सरकारी वाहनों के सरकारी प्रायोजन को उनके द्वारा प्रमाणित किये जाने एवं लॉग बुक संधारित किये जाने की शर्त पर डीजल एव पेट्रोल की वास्तविक खपत की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। न्यायिक पदाधिकारी प्रतिमाह 300 किलोमीटर सीमा के अन्दर निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।
- (vi) न्यायिक पदाधिकारियों को 10 लाख की सीमा तक Nominal Interest पर वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

VI. महँगाई भत्ता (Dearness Allowance) - राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप महँगाई भत्ता पूर्व से ही प्रदत्त है।

VII. अर्जित अवकाश नकदीकरण (Earned Leave Encashment) :-

- A. राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों/वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों का अर्जित अवकाश नकदीकरण अनुमान्य होगा।
- B. राज्य के न्यायिक पदाधिकारी/वरीय न्यायिक पदाधिकारी नकदीकरण का हकदार होगा:-
- (i) LIC का उपभोग करते समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश, जो अधिकतम सीमा 60 दिनों के अधीन अनुमान्य होगा। पदाधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में एक समय में 10 दिन तक यह सुविधा 06 बार प्राप्त कर सकेंगे।
- (ii) 02 वर्षों के ब्लॉक में 30 दिन।
- (iii) उपरोक्त (i) एव (ii) के प्रावधान सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।
- C. वैसे पदाधिकारियों जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके अवकाश नकदीकरण स्वीकृति के समय उनके द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये Leave Encashment को समायोजित करते हुए समायोजित अर्जित अवकाश के भुगतान की कार्रवाई तीन माह के अंदर की जायेगी।

VIII जल एवं विद्युत चार्ज (Water and Electricity Charges) -

- (i) प्रतिपूर्ति के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 50 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति Formula जारी रहेगा।
- (ii) विद्युत इकाई एवं जल की मात्रा के उपयोग की सीमा निम्नवत् होगी:-

Designation	Electricity	Water Quantity
District Judges	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

- (iii) यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये विपत्रों को प्रस्तुत करने के उपरांत तिमाही आधार पर की जायगी।
- (iv) बढे हुए भत्ते दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से देय होंगे।

IX उच्च योग्यता भत्ता (Higher Qualification Allowance)

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि तथा कानून में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने पर एक अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।
- (ii) कानून में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री के लिए प्रदत्त अग्रिम वेतन वृद्धि वैसी स्थिति में पदाधिकारी को दोबारा नहीं दी जायगी, यदि भविष्य में वे किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं।
- (iii) अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हीं पदाधिकारी को अनुमान्य होगी, जिसने या तो भर्ती से पहले या सेवा में रहने के बाद किसी भी समय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हो।
- (iv) यदि पदाधिकारी ने सेवा में भर्ती होने के पूर्व ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रारम्भिक भर्ती की तिथि से अनुमान्य होगी। यदि पदाधिकारी के द्वारा यदि सेवा में भर्ती होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री अर्जित की है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि डिग्री अर्जित करने की तिथि से अनुमान्य होगी।
- (v) पदाधिकारियों को उच्चतर योग्यता के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अर्धकालिक) या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की स्थिति में अनुमान्य होगी।
- (vi) अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ एसीपी चरण (ACP I या II) में भी अनुमान्य होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि तब भी उपलब्ध होगी जब पदाधिकारी को सिविल

जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) तथा सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर में पदोन्नत किया जाता है।

- (vii) अग्रिम वेतन वृद्धि जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (Entry Level) से जिला न्यायाधीश (Selection Grade) तक और जिला न्यायाधीश (Selection Grade) से जिला न्यायाधीश (Super Time Scale) तक को अनुमान्य होगी।
- (viii) अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी।

X. **गृह अर्दली/घरेलू सहायता भत्ता (Home Orderly Help Allowance) :-**

- (i). न्यायिक पदाधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता निम्न दर पर अनुमान्य होगा :-
- (a) जिला न्यायाधीश :- राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनुमान्य दर से, जो प्रतिमाह 10,000.00 रु० से अन्यून होगा।
- (b) सिविल जज - राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का 60 प्रतिशत की दर से जो प्रतिमाह 7500.00 रु० से अन्यून होगा।
- (ii). न्यायिक पदाधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।
- (iii). जिन न्यायिक पदाधिकारियों को आवासीय कर्तव्यों के लिए परिचारक/आदेशपाल/कार्यालय अधीनस्थ उपलब्ध कराया गया है, वे न्यायिक पदाधिकारी या तो वर्तमान प्रणाली को जारी रख सकते हैं या अनुशासित भत्ते का त्याग कर सकते हैं या कार्यालय परिचारक/आदेशपाल की सेवा लेने की बजाय भत्ते का दावा करने का विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- (iv). न्यूनतम वेतन के समतुल्य समेकित वेतन पर नियुक्त गृह अर्दली/आवासीय परिचारक/सेवक का पैनल तैयार करते हुए उन्हें न्यायिक पदाधिकारियों को आवंटित करने का निर्णय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा किया जायेगा और ऐसे मामलों में गृह अर्दली भत्ते का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (v). दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से घरेलू सहायता भत्ता पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 9000.00 रु० तथा पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 7500.00 रु० अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2016 से 05 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा 01.01.2021 के प्रभाव से उक्त भत्ते में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमान्य होगी।
- (vi). न्यायिक पदाधिकारी/पेंशनधारी/परिवारिक पेंशनधारियों के स्वयं प्रमाणन (Self Certification) के पश्चात् ही भत्ता अनुमान्य होगा।

XI. मकान किराया भत्ता एवं आवासीय क्वार्टर (House Rent Allowance & Residential Quarters) -

A. आवासीय क्वार्टर (Residential Quarters) -

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को उनकी पात्रता के अनुसार निशुल्क सरकारी आवास भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अथवा प्रभार ग्रहण के एक माह के अंदर उनकी माँग के अनुसार निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ii) यदि न्यायिक पदाधिकारियों को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वे निजी आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले सकते हैं :-
 - (a) यदि निजी आवास का किराया नीचे उल्लेखित अनुमान्य मकान किराया भत्ता के अन्दर है, तो किराया निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु संबंधित न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा भुगतान किये जा रहे वास्तविक किराये को प्रमाणित करना होगा।
 - (b) यदि निजी आवास का किराया अनुमान्य मकान किराया भत्ता से अधिक है, तो किराये का मूल्यांकन PWD/R&B पदाधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।
 - (c) यदि अनुमान्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किये गये किराये के बीच का अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक है तो प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान के लिए ड्राइखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त करेगा बशर्ते कि संबंधित न्यायिक पदाधिकारी अन्तर राशि का भुगतान करने के लिए तैयार न हो।

B. मकान किराया भत्ता (HRA) -

- (i) जिन न्यायिक पदाधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
- (ii) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो अपने आवास में निवास कर रहे हैं या माता-पिता या पति/पत्नी (जो लागू हो) के घर में निवास कर रहे हैं, वे उच्च न्यायालय से अपने घर में रहने की अनुमति प्राप्त करने के बाद 01.01.2016 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। साथ ही, वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो पहले से ही किराए के आवास में रह रहे हैं वे दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। भुगतान किया गया वास्तविक किराया उक्त सीमा के अधीन होगा।

- (iii) प्रधान जिला न्यायाधीश का कार्यालय या समकक्ष कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा, ऐसी स्थिति में पदाधिकारी HRA प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (iv) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप (X श्रेणी - 24%, Y श्रेणी 16%, Z श्रेणी 8%) पूर्व से ही देय है जो क्रमशः प्रतिमाह 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होगा।
- (v) महंगाई भत्ते में परिवर्तन होने पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता में निम्नवत परिवर्तन होगा:-

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of basic pay	When DA crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	09%	25%
	10%	50%

C. फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता (Furniture and Air Conditioner Allowance):-

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को प्रत्येक पाँच वर्ष में क्रय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के शर्तों के अधीन 1.25 लाख रुपये का फर्नीचर अनुदान अनुमान्य होगा। उक्त अनुदान से घरेलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं।
- (ii) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनकी सेवा दो वर्षों की हो चुकी है वे भी इस भत्ते के पात्र होंगे।
- (iii) पदाधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यह्रास दर पर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।
- (iv) फर्नीचर अनुदान के अलावा प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी के आवास पर प्रत्येक पाँच वर्ष में एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

1). आवासीय क्वार्टर रख रखाव (Maintenance):-

आवासीय क्वार्टरों के उचित रख रखाव हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक प्रधान जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के दो माह के भीतर प्रस्तावित राशि की मंजूरी राज्य सरकार प्रदान करेगी।

XII. एल.टी.सी./एच.टी.सी. (LTC/HTC) :- न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एल.टी.सी. एवं एच.टी.सी. के अधीन निम्न सुविधाएँ अनुमान्य होंगी -

- (i) LTC की सुविधा का उपभोग नहीं करने पर एक माह के वेतन का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) LTC (HTC नहीं) का उपभोग करने की स्थिति में 10 दिनों का अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमान्य होगा जिसकी अधिकतम सीमा 60 दिनों की होगी। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के ब्लॉक में 30 दिन के नगदीकरण के अतिरिक्त होगा।
- iii(a) LTC की आवृत्ति के संबंध में न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के ब्लॉक में एक LTC और एक HTC अनुमान्य होगा।
- iii(b) नव नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के पहले ब्लॉक में 2 बार HTC अनुमान्य होगा। उनके लिए 3 साल का ब्लॉक परिवीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर शुरू होगा।
- iv(a) न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी कोटि के आधार पर हवाई यात्रा अनुमान्य होगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों अर्थात् अशोक ट्रेवलस, बामर एव लॉरी और आईआर.सी.टी.सी. से खरीदे गए हों।
- iv(b) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य से निर्गत नियमों/आदेशों से शासित होंगे।
- (v) न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में कहीं भी LTC को आगे बढ़ाने की सुविधा अनुमान्य होगी।
- (vi) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को LTC/HTC की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
- (vii) न्यायिक पदाधिकारियों को LTC/HTC प्रयोजन के लिए केवल अर्जित अवकाश का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें दो दिनों की सीमा तक prefix और suffix के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने की भी अनुमति होगी।

XIII. चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance)

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रू0 3000 /- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) पेंशनधारी एवं परिवारिक पेंशनधारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रू0 4000 /- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

XIV. समाचार पत्र/पत्रिका भत्ता (Newspaper and Magazine Allowance):-

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से दो समाचार पत्रों एवं दो पत्रिकाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 1000.00 रू0 तथा सिविल जजों को दो समाचार पत्रों एवं एक पत्रिका की प्रतिपूर्ति हेतु 700.00 रू0 अनुमान्य होगा।
- (ii) प्रतिपूर्ति स्वयं प्रमाणन (Self Certification) पर अर्द्धवार्षिक आधार पर (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) की जायेगी।

XV. पोशाक भत्ता (Robe Allowance) :- झारखण्ड राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रत्येक 03 वर्ष पर 12,000.00 रू0 का पोशाक भत्ता अनुमान्य होगा।

XVI. प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष वेतन (Special Pay for Administrative work):- न्यायिक पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से निम्न रूप से विशेष वेतन अनुमान्य होगा:-

a	Principal District and Sessions Judges	Rs.7000/- per month
b	Other District Judges including I Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours	Rs. 3500/- per month.
c	District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities	Rs.3500/- per month.
d	CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers	Rs.2000/- per month.

XVII. आतिथ्य भत्ता (Sumptuary Allowance) :-

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रतिमाह 7800/- रुपये, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को 5800/- रुपये एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को 3800/- रुपये दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा।

- (ii) जिलों में प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश/सेलेक्शन ग्रेड एवं सुपर टाईम स्केल के जिला न्यायाधीश/निदेशक, न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान/सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को अतिरिक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु 1000/- रुपये का अतिरिक्त आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा।

XVIII. दूरभाष सुविधा (Telephone Facility) :-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों को उनके आवास पर निम्नरूपेण Landline एवं Broadband (सभी दर, कॉल (लॉकल एवं STD) एवं इन्टरनेट सहित) की सुविधा अनुमान्य होगी :-

1	जिला न्यायाधीश	1500/- ₹0 प्रतिमाह	1000/- ₹0 प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)
2	सिविल जज	1000/- ₹0 प्रतिमाह	750/- ₹0 प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)

- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों को मोबाइल फोन (Handset) के क्रय एवं इन्टरनेट की सुविधा निम्नरूपेण अनुमान्य होगी -

क्र०	न्यायिक पदाधिकारी	मोबाइल फोन (Handset) क्रय की सीमा	मोबाइल फोन (इन्टरनेट डाटा सहित) के उपयोग हेतु कॉल सीमा
1	जिला न्यायाधीश	30,000/- ₹0	2000/- ₹0 प्रतिमाह
2	सिविल जज	20,000/- ₹0	1500/- ₹0 प्रतिमाह

- (iii) न्यायिक पदाधिकारियों के अनुरोध पर प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार मोबाइल फोन (Handset) बदलन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (iv) न्यायिक पदाधिकारियों के पास पुराने Mobile Handset का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा मूल्य निर्धारित करते हुए Retain करने का विकल्प होगा।
- (v) वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष की सुविधा यथावत् रहेगी।

XIX. स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant) :-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर समय स्थानान्तरण अनुदान (Composite transfer grant) एक माह के मूल वेतन के समतुल्य अनुमान्य होगा।
- (ii) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को 20 किलोमीटर या उससे कम या उसी शहर में स्थानांतरण होने की स्थिति (आवास के वास्तविक परिवर्तन होने पर)

में उन्हें एक माह के मूल वेतन का 1/3 स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा।

- (iii) निजी सामग्रियों के परिवहन के लिए सातवें CPC द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुरूप वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत O.M. दिनांक 13.07.2017 द्वारा निर्धारित दर अनुमान्य होगा।
 - (iv) सड़क के माध्यम से परिवहन की स्थिति में प्रति किलोमीटर 50 रु की दर (सामग्रियों के loading/Unloading हेतु मजदूरी सहित या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो) से स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा। महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत होने की स्थिति में उक्त दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
 - (v) उपर्युक्त अनुदान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रभावी होगा।
 - (vi) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनका स्थानान्तरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुआ है और उनके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्व स्थानान्तरण अनुदान का दावा किया गया है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. कंडिका- 2(I) में वर्णित गृह अग्रिम की राशि का भुगतान व्यय शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों आदि को उधार लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम उप शीर्ष-01 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम विस्तृत शीर्ष 07 के अधीन-63 गृह निर्माण अग्रिम मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XII) में अंकित LIC भत्ता का भुगतान विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-12 छुट्टी यात्रा रियायत मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XIX) में अंकित स्थानान्तरण अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-02 यात्रा भत्ते के अधीन-13 देशीय यात्रा व्यय मद से किया जायेगा। शेष सभी भत्तों का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-01 वेतन मद से किया जायेगा।
4. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधाएँ के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प/नियम/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख झापांक-1078, दिनांक 13.02.2024 के क्रम में दिनांक 23.02.2024 की बैठक के मद संख्या-20 के रूप में दी गयी है।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

Pranveer
27/02/24
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव

ज्ञापक:-13/वरीय विविध-01/2024 का0 1459 राँची, दिनांक 27/02/24

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
27/02/24
सरकार के सचिव।

ज्ञापक:-13/वरीय विविध-01/2024 का0 1459 राँची, दिनांक 27/02/24

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मन्त्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पंयजल एवं स्वाच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव-विधि-परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड/महासचिवता, झारखण्ड, राँची/महानिबधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची/सचिव क आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

[Signature]
27/02/24
सरकार के सचिव।



GOVERNMENT OF JHARKHAND
DEPARTMENT OF PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS AND
OFFICIAL LANGUAGE

RESOLUTION

Sub: Sanction of various allowances to Jharkhand Judicial Service/Higher Judicial Service Officers - reg.

With reference to the recommendations made by the First National Judicial Pay Commission (Shetty Commission) and the orders passed in continuation to the above by the Honourable Supreme Court on 06.12.2005 and 21.02.2006 in Civil Writ Petition No. 1022/1989 (*All India Judges Association Vs Union of India and Ors*), Departmental Resolution No. 4598 dated 29.08.2006 is issued regarding the grant of allowances/facilities to the members of Jharkhand State Judicial Services/Higher Judicial Services.

2. In view of the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) and the Judgement passed in continuation to the above by the Honourable Supreme Court on 04.01.2024 in the case of W. P. (Civil) No. 643/2015 *All India Judges Association Vs Union of India and Ors*, allowances and facilities to Jharkhand Judicial Service/Higher Judicial Service Officers shall be payable as below: -

[I] **HOUSE BUILDING ADVANCE:-** In addition to the provisions laid down in House Building Advance Rules, 2017 of Government of India, the Jharkhand Judicial Service/ Higher Judicial Service Officers shall be permitted to purchase ready built house from private persons.

or

The facility of advance shall be permissible to Jharkhand Judicial Service/Higher Judicial Service Officers. The facility of House Building Advance shall be permissible at par with the Government Servants of State Government.

[II] **CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE:-** Children Education Allowance shall be permitted to every Judicial Service Officer of the state with effect from the academic year 2019-20, as below.

- i. ₹2,250/- per month as Education Allowance and ₹6,750/- per month as hostel subsidy for the education of two children up to class 12 shall be permissible.
- ii. For children with special needs, reimbursement shall be permissible at double the rate mentioned above.
- iii. When the Dearness Allowance is increased to 50%, there will be an increase of 25% in the allowance and subsidy.

Officials who are already availing this benefit, shall not be adversely affected by these recommendations.

[III] CITY COMPENSATORY ALLOWANCE:- In the light of the recommendations of the commission, City Compensatory Allowance has been abolished, but the City Compensatory Allowance already paid shall not be recovered from the concerned officials.

[IV] CONCURRENT CHARGES ALLOWANCE:-

- i. The Concurrent Charges Allowance equal to 10 percent of the minimum pay scale of the additional post held shall be permissible to the Judicial Officers of the state in case of holding the charge of that additional post beyond a period of 10 working days and performing adequate judicial work.
- ii. Jharkhand High Court will take decision regarding the grant of Concurrent Charges allowance based on the number of days worked, the quantum of judicial work turned out and the administrative work handled by the Judicial Officers.

[V] CONVEYANCE/TRANSPORT ALLOWANCE :- In supersession to the orders issued earlier, Conveyance/Transport Allowance is sanctioned to the Judicial Officers of the state, in the following manner:-

- i. The pool car facility is dispensed with. The Judicial Officers serving in the state can continue with this facility for a period of one year or more at their will, but in such case, transport allowance shall not be permissible to them.
- ii. The transport allowance given to Judicial Officers to cover the cost of maintenance of their own vehicle and the salary of driver is increased from Rs.10,000/- to Rs.13,500/- per month with effect from 01/01/2021. Transport Allowance from 01.01.2016 to 31.12.2020 shall be permissible at the rate of Rs.10000/-.
Transport Allowance at the rate of Rs.4,000/- per month shall be permitted to those Judicial Officers who have been allotted government driver or Attendant/Peon having driving skill.
- iii. In addition to Transport Allowance, reimbursement of the cost of 100 litres of petrol/diesel for cities as per Finance Department Resolution No.1994/Vi. dated 29.06.2010 and Resolution No.400/Vi dated 02.02.2017 and 75 litres of petrol/diesel in other areas shall be permissible.
- iv. An independent vehicle shall be provided to the Principal District Judge/Chief Judicial Magistrate/Director, Judicial Academy/Principal Judge, Family Court/ Secretary, District Legal Services Authority. Jharkhand High Court can curtail the above list, keeping in view the financial capacity of the state.

- v. The quantum of actual consumption of Diesel/Petrol can be increased on the condition of certification of use of official vehicle for official purposes by the Judicial Officers and maintenance of logbook. Judicial Officers can use Government vehicles for private purposes to the extent of 300 kilometres per month.
- vi. Loan facility to the extent of Rs.10 lakhs at nominal interest for the purchase of vehicle shall be provided to Judicial Officers.

[VI] **DEARNESS ALLOWANCE:-** The judicial officers of the state are already being paid dearness allowance at par with the State Government employees.

[VII] **EARNED LEAVE ENCASHMENT :-**

- A. At the time of retirement, encashment of earned leave up to 300 days shall be permissible to the Judicial Officers/Higher Judicial Officers of the state.
- B. Judicial Officers/Higher Judicial Officers of the state shall be entitled to encash:
 - i. 10 days Earned Leave while availing LTC, subject to maximum 60 days shall be permissible. The officers can avail this facility for 10 days at a time up to 06 occasions during the entire service tenure.
 - ii. 30 days in a block of 02 years.
 - iii. The aforesaid provisions (i) and (ii) shall be in addition to encashment of 300 days Earned Leave at the time of retirement.
- C. While sanctioning leave encashment of those officers who have retired, the leave encashment availed by them during their service tenure shall be adjusted and action shall be taken for the payment of earned leave so adjusted, within three months.

[VIII] **WATER AND ELECTRICITY CHARGES: -**

- i. No change will be there in the percentage of reimbursement. Reimbursement formula of 50% as recommended by the First National Judicial Pay Commission shall be continued.
- ii. The ceiling of consumption of electricity unit and quantity of water shall be as follows: -

Designation	Electricity	Water Quantity
District Judges	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

- iii. This reimbursement will be done on a quarterly basis after submitting the bills paid.
- iv. The increased allowances shall be payable with effect from 01/01/2020.

[IX.] HIGHER QUALIFICATION ALLOWANCE:-

- i. The Judicial Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e., Post-graduation in Law and one additional advance increment on acquiring Doctorate in Law.
- ii. The advance increment once granted for post-graduation or Doctorate degree in Law shall not be granted again, if in future, the officer acquires Post-graduation or Doctorate degree in any other subject.
- iii. The advance increment shall be permissible to the officer who had acquired the postgraduation or doctorate degree either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.
- iv. The advance increment shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer has already acquired the postgraduation degree or Doctorate before joining the service. The advance increment shall be permissible from the date of acquiring the degree, if the officer has acquired Postgraduation degree or Doctorate after joining the service.
- v. The advance increment for higher qualification shall be permissible to the officers in case of acquiring degree through regular studies (full time or part time) or distant learning programmes.
- vi. The benefit of advance increment shall also be permissible at ACP stage (ACP I or II). The advance increment shall be also available when the officer is promoted from Civil Judge (Junior Division) to Civil Judge (Senior Division) and from Civil Judge (Senior Division) to District Judge Cadre.
- vii. The advance increment shall be permissible in District Judge Cadre from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Timescale).
- viii. The advance increment shall be a part of the salary and dearness allowance shall be permissible accordingly.

[X.] HOME ORDERLY/DOMESTIC HELP ALLOWANCE: -

- i. The Home-cum-office orderly allowance shall be permissible to the Judicial Officers at the following rates:
 - a. District Judges - minimum wages prescribed for one unskilled worker in the state at the permissible rate, which shall not be less than Rs.10,000/- per month.
 - b. Civil Judges - 60% of the minimum wages prescribed for one unskilled worker in the state at the permissible rate, which shall not be less than Rs.7,500/- per month.
- ii. The Home-cum-office orderly allowance shall be permissible to the Judicial Officers with effect from 01.01.2020.

- iii. The Judicial Officers who have been provided with an Attender/Peon/Office Subordinate for residential duties, may exercise their option either to continue with the present system or forgo the allowance that has been the recommended or to claim the allowance instead of availing the services of office Attender/Peon.
- iv. The decision to frame a panel of Home Orderly/Residential Attender/Servant appointed on consolidated pay equivalent to minimum pay and allot them to Judicial Officers shall be taken by the Jharkhand High Court and in such cases the claim for Home Orderly Allowance shall not be permissible.
- v. Domestic Help Allowance shall be permissible at the rate of Rs.9,000/- per month to the pensioners and Rs.7,500/- per month to the family pensioners, with effect from 01/01/2016. On completion of 05 years from 01.01.2016 i.e. with effect from 01.01.2021, an increase of 30% shall be permissible in the aforesaid allowance.
- vi. The allowance shall be permissible only after self-certification by the Judicial Officers/Pensioners/Family Pensioners.

[XI] HOUSE RENT ALLOWANCE AND RESIDENTIAL QUARTERS:-

A. RESIDENTIAL QUARTERS

- i. Every Judicial Officer shall be provided with rent free Government accommodation by the House Building Department as per their eligibility or they shall be provided with private accommodation as requisitioned by them, within one month of assumption of charge.
- ii. If the Judicial Officers are not provided with Government accommodation or requisitioned private accommodation within one month, they may secure private accommodation subject to following conditions:
 - (a) If the rent of private accommodation is within the permissible House Rent Allowance mentioned below, fixation of rent will not be required, but the concerned Judicial Officer has to certify the actual rent being paid.
 - (b) If the rent of private accommodation is more than the permissible House Rent Allowance, the rent shall be assessed by the Principal District Judge with the assistance of PWD/R&B officers.
 - (c) If the difference between the permissible House Rent Allowance and the rent assessed is more than 15%, the Principal District Judge will seek the recommendation of Jharkhand High Court for the payment of the said amount, provided that the concerned Judicial Officer is not ready to pay the differential amount.

B. HOUSE RENT ALLOWANCE (HRA)

- i. The Judicial Officers who have been allotted Government accommodation shall not be entitled to House Rent Allowance.
- ii. The Judicial Officers residing in their own houses or in the house of a parent or spouse (whichever is applicable), shall be entitled to HRA recommended with effect from 01.01.2016, after obtaining permission from the High Court to reside in their own house. In addition, the Judicial Officers, already residing in hired accommodation shall be entitled to House Rent Allowance recommended with effect from 01/01/2020. The actual rent paid shall be subject to the aforesaid ceiling.
- iii. Office of Principal District Judge or equivalent office shall pay the rent directly to the landlord, in such case the officer will not be eligible to receive HRA.
- iv. House Rent Allowance to the Judicial Officers of the state is already payable at par with State Government employees (X category- 24%, Y category- 16%, Z category-8%) which shall not be less than Rs.5400/- Rs.3600/- and Rs.1800/- respectively.
- v. House Rent Allowance for Judicial Officers will be changed in accordance with the change in Dearness Allowance, as below: -

Classification of cities	Rates of HRA/p.m. as % of Basic Pay	When DA crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	09%	25%
	10%	50%

C. FURNITURE AND AIR CONDITIONER ALLOWANCE

- (a) Furniture grant of Rs 1.25 lakhs in every five years shall be permissible to every Judicial Officer on producing purchase-certificate. Household electrical appliances can also be purchased from the said grant.
- (b) The Judicial Officers having two years of service shall also be eligible for this allowance.
- (c) The option to purchase the furniture being used by the officers at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.
- (d) Apart from the furniture grant, one air conditioner shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years.

D. GOVERNMENT QUARTER - MAINTENANCE

For the proper maintenance of residential quarters, an amount of Rs Ten Lakhs will be made available to each Principal District Judge on the basis of a proposal sent by the Registry of Jharkhand High Court and the State Government will sanction the proposed amount within two months from the receipt of the proposal.

[XII] **LTC/HTC** : Under LTC and HTC the following facilities shall be permissible to Judicial Officers:

- i. In case of not availing the facility of LTC, payment of salary of one month will not be permissible.
- ii. In case of availing LTC (not HTC) encashment of 10 days Earned Leave shall be permissible subject to a maximum of 60 days. This shall be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years.
- iii. (a) With respect to frequency of LTC, the Judicial Officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 03 years.
(b) To newly recruited Judicial Officers, HTC shall be allowed 2 times in the first block of three years. For them the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation.
- iv. (a) The Judicial Officers shall be allowed to travel by air based on their grade and reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets are purchased either directly from the Airlines or from the agents authorised by the State/Central Government, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC.
(b) Other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the Rules/Orders issued by the State.
- v. The Judicial Officers shall be allowed to carry forward LTC anywhere in India after retirement for a period of one year.
- vi. The facility of LTC/HTC shall not be available to the retired Judicial Officers.
- vii. The Judicial Officers shall not be required to avail of Earned Leave only, for the purpose of LTC/HTC and they shall be permitted to avail Casual Leave as a prefix and suffix to the extent of 2 days.

[XIII] MEDICAL ALLOWANCE

- (a) Fixed Medical Allowance at the rate of Rs.3000/- per month shall be permissible to the Judicial Officers of the state, with effect from 01.01.2016.
- (b) Fixed Medical Allowance at the rate of Rs.4000/- per month shall be permissible to the pensioners and family pensioners, with effect from 01.01.2016.

[XIV] NEWSPAPER AND MAGAZINE ALLOWANCE

- (a) Rs.1000/- will be permissible to all District Judges of the state for the reimbursement of two newspapers and two magazines and Rs.700/- to the Civil Judges for the reimbursement of two newspapers and one magazine, with effect from 01.01.2020.
- (b) This reimbursement shall be on half-yearly basis (from January to June and July to December) on the basis of self-certification.

[XV] ROBE ALLOWANCE

Robe Allowance of Rs 12,000/- will be permissible to the Judicial Officers serving in Jharkhand state once in every three years, with effect from 01.01.2016.

[XVI] SPECIAL PAY FOR ADMINISTRATIVE WORK

Special pay shall be permissible to the Judicial Officers for performing additional administrative duties, with effect from 01.01.2019, as below: -

a	Principal District and Sessions Judge	Rs. 7000/- per month
b	Other District Judges including Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours	Rs. 3500/- per month
c	District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities	Rs. 3500/- per month
d	CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent courts with filling powers	Rs. 2000/- per month

[XVII] SUMPTUARY ALLOWANCE

- i. Sumptuary allowance of Rs.7800/- per month to all the District Judges of the state, Rs.5800/- per month to Civil Judges (Senior Division) and Rs.3800/- per month to Civil Judges (Junior Division) shall be permissible with effect from 01.01.2016.
- ii. Additional Sumptuary Allowance of Rs.1000/- shall be permissible to the Principal District Judge in charge of administrative functions in the Districts / District Judges in Selection Grade and Super Timescale / Director, Judicial Academy / Judicial Training Institute / Member Secretary, State Legal Services Authority / Chief Judicial Magistrate, for performing additional duties.

[XVIII] TELEPHONE FACILITIES

- i. The Judicial Officers shall be permitted Landline and Broadband [all rates including calls (local and STD) and internet] facility at their residence as below: -

1.	District Judges	Rs. 1500/- per month	Rs.1000/- per month (if Broadband facility is not available)
2.	Civil Judges	Rs.1000/- per month	Rs.750/- per month (if Broadband facility is not available)

- ii. The Judicial Officers shall be permitted the facility of purchase of mobile phone (Handset) and internet services as below-

Sl No.	Judicial Officer	Ceiling of purchase of Mobile Phone (Handset)	Ceiling of calls while using Mobile Phone (including internet data)
1.	District Judges	Rs. 30,000/-	Rs. 2000/- per month
2.	Civil Judges	Rs. 20,000/-	Rs.1500/- per month

- iii. The facility to replace the Mobile Phone (Handset) once in every three years shall be available on the request of the Judicial Officers.
- iv. The Judicial Officers shall have the option to retain the old Mobile Handset at a price determined by the Registry of High Court.
- v. Telephone facility available in office at present shall remain the same.

[XIX] TRANSFER GRANT

- (a) On transfer of Judicial Officers, the composite transfer grant equivalent to one month's basic pay shall be permissible.
- (b) Transfer grant of 1/3rd of one month's basic pay shall be permissible to the Judicial Officers of the state, if the transfer is to a place at a distance of 20 kilometres or less or within the same city (if it involves actual change of residence).
- (c) For the transportation of personal effects, the rate fixed vide O.M. dated 13.07.2017 issued by the Department of Finance, Government of India as per the recommendations of Seventh CPC shall be permissible.
- (d) In case of transportation by road, transfer grant at the rate of Rs.50/- per k.m. (including labour charges for loading/unloading or actual expenditure, whichever is less) shall be permissible. The above rate shall be raised by 25%, when the Dearness Allowance becomes 50%.
- (e) The above grant shall come into effect from 01.01.2016.
- (f) The Judicial Officers who have undergone transfer after 01.01.2016 and claimed transfer grant before revised pay scale, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay.

3. The payment of House Advance mentioned in para 2(I) shall be made from the Item 63- House Building Advance under Detailed Head 07, Expenditure Head 7610- Loans to Government Servants etc. Minor Head 201-House Building Advance Sub head-01-House Building Advance to Government Servants. Payment of LTC allowance mentioned in para 2(XII) shall be made from Item 12-Leave Travel Concession under Detailed Head-01 Pay and Allowances. Payment of transfer grant mentioned in para 2(XIX) shall be made from Item 13-Domestic Travel Expenses under Detailed Head-02 Travel Allowance. Payment of all other remaining allowances shall be made from Item 01-Pay under Detailed Head-01 Pay and Allowances.

4. Resolutions/Rules/Orders issued earlier regarding various allowances/ facilities to Jharkhand Judicial Service/Higher Judicial Service Officers shall be deemed revised to this extent.

5. Sanction of Council of minister on the proposal has been accorded as item no. 20 of the meeting of 23.02.2024 in continuation to Departmental Document Memo No. 1078 dated 13.02.2024.

Order: Ordered that this Resolution be published in the Extra Ordinary Edition of Gazette of Jharkhand.

(Praveen Kumar Topo)
Secretary to Government

Memo No.13/Vareey Vividh-01/2024 Ka. 1459

Ranchi, Dated 27.02.2024

Copy to: Joint Secretary-Cum-Nodal Officer, E-Gazette, Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Language, Jharkhand, Ranchi, sent for publication in E-Gazette.

/-
Secretary to Government

Memo No.13/Vareey Vividh-01/2024 Ka. 1459

Ranchi, Dated 27.02.2024

Copy to: The Accountant General, Jharkhand, Ranchi/Additional Chief Secretary, Department of Energy, Jharkhand, Ranchi/Principal Secretary, Cabinet Secretariat and Vigilance Department, Jharkhand, Ranchi/Principal Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Jharkhand, Ranchi/Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Jharkhand, Ranchi/Secretary, Department of Finance, Jharkhand, Ranchi/Secretary, Building Construction Department, Jharkhand, Ranchi/Secretary, Transport Department, Jharkhand, Ranchi/Principal Secretary, Legal Consultant, Department of Law, Jharkhand, Ranchi/Joint Secretary, Chief Secretary Cell, Jharkhand/Advocate General, Jharkhand, Ranchi/Registrar General, Jharkhand High Court, Ranchi/ Private Secretary to Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Language, Jharkhand, Ranchi, sent for information and necessary action.

/-
Secretary to Government